से रियायती दर पर वित्त की सुविधाएं मिली हुई है । इसके अलावा, इस क्षेत्र के उदयपुर जिले में केन्द्रीय निवेश राज-सहायता दी जाती है ।

राष्ट्रीय विकास परिषद की मुख्य मंत्रियों की समिति में लिये गये निर्णय के अनुसरण में योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारो के परामर्श से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों का पता लगाया गया था । इस प्रयोजन के लिये लागू मानदण्डो के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित नही किया गया था । पिछडे क्षेत्रों के समस्त प्रश्न को देखते तथा समस्या के प्रभावी रूप से निपटाये जाने हेतु प्रभावी सुझाव देने के लिये योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता मे एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई है । समिति द्वारा सिफारिशें पेश किये जाने तथा सरकार द्वारा उन पर विचार कर लिये जाने के बाद ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलो/क्षेत्रों की वर्तमान सूची में कोई परिवर्तन किया जा सकेगा ।

Zonal Council Meeting held in Trivandrum

1308. SHRI A A. RAHIM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the concrete steps taken to implement the recommendations/conclusions arrived at the Zonal Council meeting held in Trivandrum in September last;

(b) whether Kerala Government has stressed for giving more assistance for developing tribal/plantation areas in Kerala; and

(c) if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Implementation of the recommendations made by the Southern Zonal Council in its last meeting will be taken up as soon as the proceedings of the meeting, which have been sent for comments of the member-States, are issued formally.

(b) No, Sir.

(c) Dos not arise.

गुजरात को सीमेंट की सप्लाई

1309. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य को अप्रैल, 1980 से सितम्बर, 1980 के बीच, उसकी माँग की तुलना में कितनी सीमेंट आवटित की गई और अक्तूबर से दिसम्बर के लिए कितनी;

(ख) उक्त मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) देश के अन्य राज्यों को की गई सप्लाई की तुलना मे गुजरात राज्य को कितनी सीमेट का आवंटन किया गया;

(घ) इस तथ्य को देखते हुए कि सीमेंट का उत्पादन देश की आवश्यकता को पूरा नही कर पा रहा है विदेशो से सीमेट का आयात न करने के क्या कारण है; और

(ङ) वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान विदेशों से कितनी सीमेंट का आयात किया गया, और उपरोक्त अवधि के दौरान देश का वार्षिक उत्पादन तथा मांग क्या रही ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना): (क) अप्रैल से दिसम्बर 1980 तक की तीन तिमाहियों में गुजरात राज्य

राज्य को आवंटित किए गए सीमेंट की मात्रा निम्न प्रकार है :—

अवधि	मूल आवंटन (मी० टनों में)	तदर्थ अतिरिक्त आवंटन	कुल
1980 की द्वितीय तिमाही (अप्रैल-जून)	330000	37000	367000
1980 की तृतीय तिमाही (जुलाई-सितम्बर)	346500	30000	376500
1980 की चौथी तिमाही (अक्तूबर-दिसम्बर)	346500	50000	396500

सीमेंट के लिए राज्यों की मागों को एकत्रित नहीं किया जाता है। किन्तु गुजरात के मुख्य मंत्री ने हाल ही में 1980 की चौथी तिमाही (अक्तूबर-दिसम्बर) के लिए राज्य सरकार को आवंटन बढ़ाकर 7 लाख मी० टन तक करने का अनुरोध किया है।

(ख) देश में सीमेंट की उपलब्धता मांग की अपेक्षा कम है। गुजरात सहित अन्य राज्यों को अतिरिक्त आवटन करना देश में सीमेंट की उपलब्धता संबंधी स्थिति में सुधार होने पर ही संभव होगा जिसके लिए हर सभव प्रयत्न किये जा रहे है।

(ग) अप्रैल-जून और जुलाई-सितम्बर, 1980 के दोरान सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रो को किए गए सीमेंट के आवंटन और प्रेषणों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये LT सख्या 14420/80]

(घ) बंदरगाहों की सीमेंट लाने ले जाने की क्षमता और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए काफी हद तक सीमेंट का आयात किया जा रहा है।

(ङ) वर्ष	आयातित सीमेंट की मात्रा	स्वदेशी उत्पादन	सीमेंट संबंधी कार्यकारी दल द्वारा अनुमानित मांग
			(लाख मी० टनों में)
1978-79	16.55	194.2	240.00
1979-80	15.47	176.2	259.20
1980-81	10.32*	*101.2 (अनु.)	279.90

*अप्रैल-अक्तूबर, 1980 के लिए।